पहली तिमाही में 9 सेक्टरों में करीब 2 लाख रिक्तियां

इंदिवजल धस्माना नई दिल्ली, 28 सितंबर

कशल कामगारों की कमी सहित अन्य वजहों से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 9 सेक्टरों में करीब 1,87,062 रिक्तियां हैं। नए संशोधित तिमाही रोजगार सर्वे (क्यूईएस) के आंकड़ों से यह जानकारी मिलती है।

यह अप्रैल-जून, 2021-22 तक इन प्रतिष्ठानों द्वारा दी गई कुल नौकरियों के 0.6 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है। इन 9 क्षेत्रों में विनिर्माण, निर्माण ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्टोरेंट, आईटी-बीपीओ और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं, जिनमें 308 लाख लोग काम करते हैं।

इन रिक्तियों में विनिर्माण की

हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है क्योंकि इस अवधि के दौरान यहां 99,429 रिक्तियां भरी जानी हैं। विनिर्माण क्षेत्र के करीब 4.5 प्रतिप्तानों ने रिक्तियां बताई हैं। आईटी-बीपीओ में भी इतने ही प्रतिष्ठाननो ने इस अवधि के दौरान रिक्तियां बताई हैं। जनाय से प्राप्त प्रतिस्था वर्षाह है। बहरहाल कुल मिलाकर देखें तो इस सेक्ट्र के सिर्फ 2,793 प्रतिष्ठानों में रिक्तियां हैं।

इन रिक्तियों की वजह इस्तीफे, सेवानिवृत्ति, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता न होना है। चार्ट में कुशल कामगारों के अभाव को अन्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। सर्वे रिपोर्ट के आकड़ों के मुताबिक इस श्रेणी में 39 प्रतिशत रिक्तियां हैं।

काना है। आल इंडिया सर्वे के विशेषज्ञ समूह के चेयरमैन एसपी मुखर्जी ने

ने कुशल श्रमिकों की कमी को रिक्तियों की मुख्य वजह बताई, उसके बाद सेवानिवृत्ति व इस्तीफे आते हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे के परिणाम जोर देते हैं कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को इस क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत

सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 18 प्रतिशत प्रतिष्ठान औपचारिक कौशल विकास कार्यक्रम चलाते हैं, जो अधिकतर उनके अनपे कर्मचारियों के लिए होता है। प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों में

आईटी/बीपीओ क्षेत्र पहले स्थान पर (29.9 प्रतिशत) है, जिसके बाद वित्तीय सेवा (22.8 प्रतिशत) और शिक्षा क्षेत्र (21.1 प्रतिशत)

रिक्तियों की रिथति

सक्टर	शक्त बतान वाल	कुल ।राक्तया	रायतया का वजह (प्रातशत म)		
	प्रतिष्ठान (%)		इस्तीफा	सेवानिवृत्ति	अन्य
विनिर्माण	4.5	99429	31.7	19.8	48.5
निर्माण	0.9	3400	2.1	3.1	94.8
ट्रेड	2.5	8400	36.8	7.3	55.9
ट्रांसपोर्ट	3.4	26500	41.3	56.9	1.9
शिक्षा	4.4	36600	23	41.2	35.9
स्वास्थ्य	2.6	5900	71.6	6.6	21.8
रेस्टोरेंट	1.8	3000	68.8	16.5	14.7
आईटी/बीपी	ओ 4.5	2800	38.7	0.7	60.6
वित्तीय सेवा	0.6	700	33.7	55.7	10.6
कुल	3,6	187062	33	27.7	39,9
योत∙ शस ठ	गरो का गडला संशो	शिव विसादी जेन	रागाण ज्यारी		

सरकार ने घटाए 22,000 से ज्यादा अनुपालन

बीएस संवाददाता नई दिल्ली 28 सितंबर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि कई कानूनों के सरलीकरण, उनको समाप्त करने और उनके गैर-अपराधीकरण के जरिये अनुपालन बोझ को कम करने के सभी प्रयासों और उपायों का व्यापार सुगमता में एक परिवर्तनकारी और प्रभावकारी

असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि अनुपालन बोझ में कमी हर कारोबार, व्यक्ति और नागरिक में विश्वास से जुड़ी है। मंत्री ने अनुपालन के बोझ को

कम करने के विषय पर आयोजित कार्यशाला में कहा,

अनपालनों में कमी जिसमे अनपालन का सरलीकरण, कई अनुपालनों का उन्मूलन, कई कानूनों का गैर-अपराधीकरण शामिल है। सामूहिक रूप से जब आप इसे देखें तो इसका परिवर्तनकारी असर हो सकता है और व्यवसाय करने में आसानी पर

इसका कई गुणा प्रभाव पड़ता है।' उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि केंद्र व राज्यों ने 22,000 से ज्यादा अनुपालन कम किए हैं।

करीब 13,000 अनुपालनों का सरलीकरण किया गया है, जबकि 1 200 से ज्यादा प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया है।

यूपी में मोसमी फलों से बनेगी वाइन बीएस संवादतात लखनऊ, 28 सितंबर प्रोत्स हैंडिया वाइन इस्ताइयों की स्थापना के लिए ऑल ईंडिया वाइन

उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले आम, जामुन, अमरूद जैसे तमाम मौसमी फलों का इस्तेमाल उम्दा क्वालिटी की वादन बनाने में किया जाएगा। सुला, गाडसन, गुड ड्राप सहित कई मशहूर देशी वाइन निर्माता कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में अपनी इकाई लगाने में रुचि दिखाई है।

प्रदेश सरकार अपनी महत्त्वाकांक्षी वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) के तहत भी ऐसे जिलों को चिह्नित करेगी, जहां कोई खास फल बड़े पैमाने पर पैदा होता है। इन जिलों में वाइनरीज की स्थापना को ओडीओपी के तहत

पोडयशर एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित विभिन्न प्रदेशों की वाइन उत्पादक इकाइयों इंडोस्प्रिट, गाडसन आर्गेनिक्स फार्म, बरेली, गुड डाप सेलर सुला विनियार्ड के प्रतिनिधियों अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी और आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी से मुलाकात की।

नई आबकारी नीति में जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव, आबकारी ने कहा कि प्रदेश में सब-ट्रापिकल फलों जैसे आम, जामुन, कटहल, अमरूद, अंगूर, लींची, आंवला, पपीता आदि का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसकी खपत पूरी तरह से नहीं हो पाती है, साथ ही फलों के समुचित भंडारण की सुविधा के अभाव में रख-रखाव न हो पाने से भारी मात्रा में फल शीव्र खराब होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि नर्ड नीति के तहत किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य दिलाने के लिए वाइनरी की स्थापना मददगार माबित होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में वादनरी स्थापित करने संबंधी नियमावली पहले 1961 व फिर 2001 में बनाई गई थी। हालांकि, इसके बाद भी प्रदेश में एक भी वाइन उत्पादन की इकाई की स्थापना नहीं हो सकी है। जबकि महाराष्ट्र के पुणे व नासिक में इनकी तादाद दर्जनों में है। संजय ने बताया कि वहां की वाइनरी के खरीद कर वाइन का उत्पादन हो रहा है।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE
AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUSCENSIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION,
DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

UMA EXPORTS LIMITED

Corporate Identification Number: U14109WB1988PLC043934

Uma Exports Limited ("Company" or "Issuer") was originally incorporated as "Uma Exports Private Limited" on March 19, 1988 as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Register of Companies, West Bengal Pursuant to a special resolution of our Shareholders passed in an order-ordering repert and the December 14, 2009, or Company was covered from a private inhetic company to a public limited company and the name of our Company as changed to *Uma Exports* Limited and a fresh certificate of incorporation dated March 25, 2010, or consequent to such name change was issued to our Company by the Register of Companies Company (or Company) as "Exports Company" and the Company of the Register of Companies (or Company) and the Company of the Register of Companies (or Companies Company) and the Company of the Register of Companies (or Companies Company) and the Register of Companies (or Companies) and Register of Companies (or Companies)

Registered Office: Ganga Jamuna Apariment, 28/1 Shaksspeare Sarani, 1st Floor, Kolkata – 700017, West Bengali Telephone: +91 33 22811396 / 7 Contact Person: Srifi Singh Roy, Company Secretary and Compilance Officer E-mail: cs@umaexports.net.in; Website: www.umaexports.net; Corporate Identity Number: U14109Wi51988PLC043

PROMOTERS OF THE COMPANY: RAKESH KHEMKA AND SUMITRA DEVI KHEMUKA

E-mail c. 26(mail-apperts and in. Website: www.unaexports.net. Corporate Identity Number: 114 109/W1968/ELCH3934

PROMOTERS OF THE COMPANY: RAKESH KHEMKA AND SUMITER DEV KHEMUKA

INITIAL PUBLIC OFFIRING FUTP (0) • [EDUTY SHARS 6) FOF FACE VAILE ? 10 EACH (*COUNTY SHARS; (1) FALLE * 10 EACH (*COUNTY SHARS; (1) EACH (*COUNTY SHARS) (1) FALLE * 10 EACH (*COUNTY SHARS; (1) EACH (* 1) E

p.m. on the 21" day from the aforesaid date of filing the DRHP with SEB.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the issue unless they can afford to take the risk of losing their endire investment. Investments are advised to read for risk and investors should not invest any funds in the issue unless they can afford to take the risk of losing their endire investment. Investors are advised to read for risk actions carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Secretizes and Exchange Board of India (SEBP), not dees SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the DHR fill defining hospectus. Specific attention of the investor is similar to the invest in the Equity Shares described in the IDRHP and profit in the PRP of the PRP

NSE. For details of the share capital and capital structure of the Company, see "Capital Structure" on page 64 of the DRHP Makesh Khemukk and Ajay Roy Chowdhury are the signatories to the Memorandum of Association of our Company who subscribed to 20 (Twenty) Equity Share each, bearing face value of ₹10- each at the time of such subscription. The lability of the members of our Company is influed. For details of the man objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see the chapter title" History and Certain Corporate Matters" on page 120 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER REGISTRAR TO THE ISSUE **EC**v

Corporate Capital Ventures

Corporate CapitalVentures Private Limited

160, Basement Vinoba Puri, Laipat Nagar - II, New Delhi - 110024,

Tet: +9 111 - 41824066; Fax: +91 11 - 41824066

Email: kp@ccvindia.com

Website: www.cevindia.com SEBI Registration: INM000012276 Validity: Permanent Contact Person: Mr. Kulbhushan Parashar

MAS Services Limited
T-34, 2nd Floor, Okiha Industrial Area, Phase - III, New Delhi - 110020, India;
Telepine: + 91 11 - 26387281/82/83; Fax: + 91 11 - 26387384
Tenahil IDininGo@masserv.com Website: www.masserv.com
SEBI Registration: NR 000000049

Validity: Permanent Contact Person: Mr. Sharwan Mangla

alized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHA

Date: September 28, 2021

UNIX : VUXSSOVIDE

UNIX : VUXSSOVID

UNIX : VUXSSOVID

UNIX : VUXSSOVID

UNIX : VU

आंकड़ों की निजता व सुरक्षा अहम

नई दिल्ली, 28 सितंबर

∙कड़ों की निजता अप कड़ों की निजता और ग्राहकों के आंकड़ों की सुरक्षा के महत्त्व पर जोर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत में फिनटेक की स्वीकार्यता की दर उच्च स्तर पर है, जिसकी तुलना में वैश्विक औसत बहुत नीचे है।

. ७ . फिनटेक उद्योग के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि भारत में डिजिटल लेनदेन का मुल्य जनवरी-अगस्त 2021 में बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले सला 4 लाख करोड़ रुपये और 2019 में 2 लाख करोड़ रुपये था। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, 2021

को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा, 'डेटा की निजता बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस मुद्दे पर काफी भिन्न विचार हो सक्द्रो हैं। बहरहाल इसके मूल में निजता का सम्मान है, जैसा कि दिशानिर्देश के सिद्धांत में कहा गया है।' उन्होंने कहा कि ग्राहकों के आंकड़ों की सुरक्षा विश्वास बहाली की रीढ़ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'जब तक मेरे आंकडों की बेहतर तरीके से सुरक्षा नहीं होती, मैं इन योजनाओं से जुड़ना नहीं जाना चाहुंगी। इसलिए यह

दिशानिर्देश सिद्धांत है।' भारत में फिनटेक स्वीकार्यता दर 87 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक औसत 64 प्रतिशत है। वित्त मंत्री ने कहा, 'मुझे लगता है कि भारत डिजिटल गतिविधियों. डिजिटल

भुगतान का प्रमुख केंद्र है।' इस कार्यक्रम के दौरान जिम्मेदार डिजिटल भगतान के लिए संयक्त

■भारत में डिजिटल लेनदेन का मृल्य जनवरी-अगस्त. 2021 में बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपये हो गया

■देश में फिनटेक स्वीकार्यता दर 87 प्रतिशत है, जबकि वैश्विक औसत ६४ प्रतिशत

■रिपोर्ट में वित्तीय प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी पर भी जोर

राष्ट्र सिद्धान्तों पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई। इसमें सरकार प्रयोगकर्ताओं. उद्योग और कंपनियों को निर्देशित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में वित्तीय प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी पर भी जोर दिया गया है। सीतारमण ने कहा, 'यह रिपोर्ट

जारी की गई है। इससे मैं काफी प्रभावित हूं। यह समय की जरूरत है। हमें यह समझने की जरूरत है कि अंतरप्रचालन वाली प्रणाली को लाने की हमारी इच्छा के लिए एक तंत्र को आगे बढ़ाने की जरूरत है. क्योंकि इसमें पारदर्शिता होगी। हमें इन चीजों पर समझौता करने की जरूरत नहीं है।'

फिनटेक पर नजर

का नियमन : रवि शंकर **अनूप रॉय** कोलकाता, 28 सितंबर भागनीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

के आधार से अधिक इकाई के आधार होना चाहिए। गूगल और एमेजॉन की ओर से जमा उत्पादों की सुविधा देने के क्षेत्र

होती है।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2021 में रिव शंकर के मुख्य भाषण में कई बार बड़ी तकनीकी कंपनियों और उनके नियमन के बारे में उल्लेख किया गया।

उन्होंने कहा कि चूंकि फिनटेक

कंपनी के आधार पर हो फिनटेक

के डिप्टी गवर्नर टी रवि शंकर ने कहा है कि फिनटेक कंपनियों पर रिजर्व बैंक का नियमन गतिविधि

में उतरने की घोषणा के बाद पहली बार रिजर्व बैंक के किसी वरिष्ठ अधिकारी ने बड़ी तकनीकी कंपनियों पर नियमन को लेकर बयान जारी किया है। जमा क्षेत्र पर बैकिंग नियामक की विशेष नजर

अपने भाषण के दौरान उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि क्यें फिनटेक को जमा के क्षेत्र में उतरने की अनुमति नहीं है और वे केवल भुगतान सेवा प्रदाता हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई फिनटेक कंपनी ऋण और जमा उत्पादों जैसी तरलता सेवाएं मुहैया कराती है तो उनका विनियमन अन्य तरलता सेवा प्रदाताओं जैसे कि बैंक की तर्ज पर कठोर होना चाहिए।

समचे बैंकिंग परितंत्र में बदलाव ला रही है लिहाजा नियमन भी उसी के अनुरूप बनाना होगा। फिनटेक कंपनियों के काम में व्यापक विविधता को देखते हुए नियामकीय दायरे को विस्तारित करने की अत्यंत

आवश्यकता है। डिप्टी गवर्नर ने कहा, 'नियमन के दृष्टिकोण में भी विनियमित किए जाने वाले संस्था के प्रकार को शामिल करने की जरूरत है। एक ओर जहां अधिकांश मामलों में समान तरह की गतिविधियों में एक जैसे नियमन को लागू करना चाहिए वहीं जब बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले वित्तीय गतिविधि के नियमन की बात आती है तो हो सकता है कि इकाई आधारित नियमन के मुकाबले

गतिविधि आधारित नियमन कम

प्रभावा हा। ऐसे समय पर जब साइबर सुरक्षा जोखिमों ने सभी के लिए वित्तीय जोखिमों को बढ़ा दिया है तब बड़े आकार की वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचा इकाइयों या बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ व्यवहार करते समय प्रणालीगत जोखिम परिचालन जोखिम और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले जोखिम सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी तकनीकी कंपनियों के कदम रखने से वित्तीय और गैर-वित्तीय कंपनियों के बीच का अंतर तेजी से धुंधला होता जा रहा है और अब इनके बीच कोई

सीमा नहीं रह गई है। डिप्टी गवर्नर ने कहा, 'नियमन को बदलाव की प्रक्रिया को धीमा करने के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है ताकि किसी प्रणाली को उसे अपनाने और नए स्वरूप में सामने आने का वक्त मिल जाए।

कच्चे तेल में तेजी से पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े

त्वेष मिश्र

नई दिल्ली, 28 सितंबर

कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से पेट्रोल व डीजल के घरेलू दाम नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। आज पेट्रोल की कीमत में 20 पैसे लीटर और डीजल की कीमत में 25 पैसे

प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। आज की बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेटोल 101,39 रुपये प्रति लीटर और डीजल

न्द्रारा 101.39 रुपय द्वारा साहर जार आवार 57 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोल का अधिकतम बिक्री मूल्य 101.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल का 89.87 रुपये प्रति लीटर रहा है। इस स्तर पर कीमतें जुलाई में बनी रहीं और अगस्त, 2021 में इसमें कुछ कमी आई। कच्चे तेल के इंडियन बास्केट. जिस कमा आहा कच्च तल क झड़थन बास्कट, ाजस भाव पर भारत के तेलशोधक कच्चा तेल लेते हैं, की कीमत जुलाई में 71,63 जॉलर प्रति बैरल और अगस्त में 73.46 डॉलर प्रति बैरल रही। पेट्रोलियम प्लानिंग ऐंड एनॉलिसिस सेल के



मुताबिक 27 सितंबर को इसकी कीमत 76.89 डॉलर प्रति बैरल रही।

ब्रेंट क्रूड, जो वैश्विक तेल के 80 प्रतिशत कारोबार का मानक है, मंगलवार को 80 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। 1 सितंबर को यह 71.59 डॉलर प्रति बैरल पर था। ऑर्गेनाइजेशन आफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (ओपेक) की ओर से आपर्ति की ओर से चिंता और ब्रहती मांग पूरी न हो पाने के कारण यह तेजी आई है।

उपभोक्ताओं के हिसाब से देखें तो कच्चे तेल की कीमत में 1 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी होने पर पेट्रोल व डीजल के दाम में क्रमश: 30 पैसे और 50 पैसे की बढ़ोतरी होती है।

वैश्विक तेजी के साथ तेल कंपनियों ने 24 सितंबर, 2021 से डीजल के खुदरा दाम में बढ़ोतरी शुरू की। इसके पहले 15 जुलाई, 2021 को डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई थी। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी को तेल कंपनियों ने मंगलवार तक रोके रखा। पेटोल के दाम में आखिरी बार बढ़ोतरी 17 जुलाई, 2021 को की गई थी।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी के एक अधिकारी के मुताबिक, 'कच्चे तेल की कीमत करीब 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। वैश्विक उत्पादन में व्यवधान की वजह से ऊर्जा कंपनियों को अपने स्टॉक का तेल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसी वजह से अमेरिका के कच्चे तेल का भंडार तीन साल के निचले स्तर

बीएस सूडोकू 4164 परिणाम संख्या 4163

5 6 2 9 6 8 3 9 2 5 1 7 4 6 8 5 9 4 8 7 1 6 2 3 4 2 1 6 8 3 5 4 9 8 6 1 8 5 9 कैसे खेलें? हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 4 2

जेड मोड़ सहित 20 सुरंगों पर चल रहा हैं काम

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर बनाई जा रही 6.5 किलोमीटर की जेड-मोड़ सुरंग के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। यह सुरंग रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्त्वूपर्ण है।

इस मौके पर गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय जम्मू–कश्मीर में 32 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 20 सरंगों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा लद्दाख में 20 किलोमीटर की 11 सुरंग का निर्माण चल रहा है।